भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं.1359

(जिसका उत्तर सोमवार 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

भारत के राजकोषीय और मुद्रास्फीति परिदृश्य का मूल्यांकन

1359. **प्रो. सौगत राय:**

श्री किशोरी लाल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार का भारत के राजकोषीय और मुद्रास्फीति परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय अनुमानों में किसी संशोधन पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाहरी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के विरूद्ध अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): पिछले पांच महीनों में वैश्विक आर्थिक स्थिति अस्थिर रही है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें (ब्रेंट) अप्रैल, 2026 में 138.2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के शिखर से घटकर जुलाई 2026 में 68.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गई हैं और वर्तमान में 20 जुलाई 2026 को लगभग 87.0 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अनुसार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभाव सूचकांक अप्रैल 2026 में 1.84 से घटकर जून 2026 में 1.25 हो गया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थितियों में सुधार को दर्शाता है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दबावों में कमी से आयातित मुद्रास्फीति के दबाव, सीमित इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने और भारत के राजकोषीय और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को समर्थन मिलने की उम्मीद है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सुचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत पर दर्शायी गयी है, जबकि यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण वैश्विक कमोडिटी मूल्य आंदोलनों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से ऊपर के जोखिमों के अध्यधीन रहता है। राजकोषीय स्तर पर, सरकार वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, सरकार उभरते वैश्विक घटनाक्रमों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके निहितार्थों की गहन निगरानी कर रही है, और वृहद आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए यथा आवश्यक उचित नीतिगत उपाय कर रही है।

(घ) सरकार ने बाहरी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के खिलाफ अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। कच्चे तेल के आयात स्त्रोतों के विविधीकरण, कार्यनीतिक साझेदारियों का विस्तार, कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों का संवर्धन, वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण ऊर्जा इनपुट का घरेलू उत्पादन और कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण योजना के कार्यान्वयन जैसी विविध कार्यनीतियों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में बदलने हेतु प्रोत्साहित करने जैसी मांग-पक्ष पहल भी की गई है। व्यापार और उद्योग का समर्थन करने के लिए, आरईएलआईईएफ (निर्यात सुविधा के लिए प्रतिरोधक और लॉजिस्टिक पहल) योजना, भारत समुद्री बीमा पूल, आरओडीटीईपी (निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट) लाभों की बहाली, सीमा शुल्क की शीघ्र मंजूरी, लॉजिस्टिक सुविधा, लक्षित सीमा शुल्क राहत और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 जैसे उपाय शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार मुक्त व्यापार करारों और व्यापक आर्थिक भागीदारी/सहयोग करारों के अपने नेटवर्क का विस्तार करके व्यापार समुत्थानशीलता को सुदृढ़ कर रही है।

सरकार ने सुनिश्चित गैस आपूर्ति, आयात स्रोतों के विविधीकरण, अग्रिम खरीद और बफर स्टॉक के रखरखाव के माध्यम से उर्वरकों और अन्य आवश्यक कृषि आदानों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। इन प्रयासों को विदेशी क्षेत्र के प्रतिरोधक को सुदृढ़ करने और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) फ्रेमवर्क के उदारीकरण, विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों, विशेष स्वैप सुविधाओं और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देने के माध्यम से विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को समर्थन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहलों द्वारा पूरक किया गया है। साथ में, ये समन्वित उपाय भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करते हैं और बाहरी झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता को कम करते हैं।

*****